अरावली पहाड़ियों के लिए व्यापक योजना

2003. **श्री संतोष बागड़ोदिया** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने जापान के सहयोग से अरावली पहाड़ियों को हरा-भरा बनाने की एक व्यापक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना का कार्यान्वयन कब तक शुरू किए जाने की संभावना है और इस संपूर्ण योजना पर कितनी वार्षिक लागत और कुल कितना अनुमानित खर्च आने की सम्भावना है; और

(घ) क्या सरकार इस योजना को देश के अन्य भागों में भी लागू करने का विचार रखती है; यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (ग) जापान सरकार (ओ०ई०सी०एफ०) राजस्थान में अरावली पहाड़ियों की वनीकरण परियोजना हेतु सहायता देने के लिए सहमत हो गई है। 166.85 करोड़ रु० की लागत वाली यह परियोजना राजस्थान के दस जिलों में वर्ष 1992-93 से 1996-97 तक कार्यान्वित की जाएगी। परियोजना के अन्तर्गत चलाए जाने वाले कार्यकलापों में वनीकरण, अवक्रमित वनों का पुनर्वनीकरण, मुद्रा संरक्षण, सिल्वी चारागाह, फार्म वानिकी, वन्यजीव आवास सुधार आदि शामिल हैं। परियोजना की वर्षवार स्थिति निम्नप्रकार है:—

वर्ष	रुपये (करोड़ में)
1992-93	14.66
1993-94	28.49
1994-95	39.46
1995-96	48.90
1996-97	35.34

(घ) ओ०ई०सी०एफ० द्वारा सहायता प्राप्त अरावली पहाड़ियों की परियोजना राजस्थान तक ही सीमित है।

Cyanide Mud Residue from the Kolar Gold Mines

2004. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the cyanide mud residue from the Kolar gold mines is dangerously polluting drinking water and crops around the Kolar gold fields; and

(b) if so, what measures Government have taken to check the pollution?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS (SHRI KAMAL NATH) : (a) and (b) Karnataka State Pollution Control Board have informed that about 1162 acres of land around Kolar Gold Field is affected due to tailing dumps of Bharat Gold Mines Limited. Chemical analysis of drinking water samples in the area has not indicated any contamination due to Cyanide. There is no report of any damage to nearby crops.

World Bank Assistance for development of Forests and National Parks in Andhra Pradesh

2005. DR. NARREDDY THULASI REDDY:
DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY:

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government have received a project report from the Government of Andhra Pradesh for getting World Bank assistance for the development and protection of forest/Social forestry and setting up of National Parks in Andhra Pradesh; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH) : (a) Yes, Sir.

(b) A project proposal has been received from the State Government of Andhra Pradesh for obtaining World Bank assistance for development of the forestry sector. The total cost of the project is Rs. 334.59 crores and is proposed to be implemented over a period of five years. the project activities include regeneration of degraded forests, social forestry, forest protection, development of protected areas, research, training and communication etc. The project proposal is to be appraised by the World Bank.

लम्बित ताप विद्युत परियोजनाएं

2006. **डा० बापू कालदाते** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों से प्राप्त ताप विद्युत परि-

योजनाओं, नदी घाटी परियोजनाओं, पन बिजली परियोजनाओं, औद्योगिक परियोजनाओं, खनन परियोजनाओं तथा अन्य परियोजनाओं के ऐसे कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो 1 जनवरी, 1992 को सरकार के पास लम्बित थे;

(ख) इस तरह लम्बित परियोजनाओं में से ऐसी परियोजनाओं के नाम और संख्या क्या है, जो अपेक्षित शर्तों को पूरा करती है;

(ग) ऐसी परियोजनाओं को सरकार द्वारा कब तक स्वीकृत किये जाने की सम्भावना है; और

(घ) इस तरह लम्बित परियोजनाओं में से ऐसी परियोजनाओं की संख्या कितनी है, जो अपेक्षित शर्तों को पूरा नहीं करती हैं और उनका ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) 1.1.1992 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों से कुल 93 परियोजनाएं 15 ताप विद्युत, 6 पन विद्युत, 31 औद्योगिक, 25 खनन तथा 16 अन्य परियोजनाएं पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लंबित हैं।

(ख) और (ग) जिन 10 परियोजनाएं जिनके बारे में मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है उनसे संबंधित एक विवरण संलग्न है **(नीचे देखिये)** पहली 9 परियोजनाओं पर कार्रवाई पहले ही पूरी कर ली गई है और इस संबंध में अन्तिम निर्णय शिघ्र लिए जाने की आशा है। अंतिम परियोजना नामतः कच्छ का खाड़ी में सेकिंड सिंगल बाय मूरिंग के बारे में निर्णय वन भूमि को उपयोग में लाने के ब्यौरे प्रस्तुत किए जाने के बाद ही लिया जा सकता है।

(घ) 1.1.1992 की स्थिति के अनुसार बाकी बची 83 लंबित परियोजनाओं में से 23 को मंजूरी दी जा चुकी है, 7 परियोजनाओं को नामंजूर कर दिया गया है और एक परियोजना को इसके प्रस्तावक द्वारा वापस ले लिया गया है। शेष 52 परियोजनाओं के संबंध में अपेक्षित पर्यावरणीय आंकड़े और कार्य योजनाएं भेजी जानी हैं और इनके प्राप्त होने पर ही इन पर निर्णय लिया जा सकेगा।

विवरण

क्र०सं०	परियोजना का नाम	टिप्पणी
क.	**औद्योगिक परियोजनाएं**	
1.	साल दीघुरम में फास्फेटिक फर्टिलाइजर परियोजना—पाराडीप फास्फेट्स और रासायन लि०	कार्रवाई की जा रही है।
2.	औरिया में गैस क्रैकर काम्पलेक्स —गैस अथारिटी आफ इंडिया लि०	-वही-
3.	एन्टीबाइटिक्स यूनिट में डी जी सैटों की स्थापना—इंडियन ड्रग्स एंड फार्मेस्यूटिकल लि०	कार्रवाई की जा रही है।
4.	दिल्ली में मारूति उद्योग लिमिटेड तक पाइप लाइन—गैस अथारिटी आफ इंडिया	-वही-
ख.	**खनन परियोजनाएं**	
5.	राजरप्पा ओपन कास्ट खान—सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड	-वही-
6.	ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि० की जामबाद खुली खादान परियोजनाएं	-वही-
ग.	**अन्य परियोजनाएं**	
7.	पारादीप पत्तन में कोल हैंडलिंग सुविधाएं	-वही-
8.	पोर्ट ब्लेयर में डर्थ 3 और 4 हाडा ह्वार्ट	-वही-
9.	निचली और उच्च जल लाइन के बीच पोर्ट ब्लेयर अल्बरडन जेटी में रैम्प का निर्माण	-वही-
10.	कच्छ की खाड़ी में सेकिंड सिंगल बाय मूरिंग-इंडियन आयल कार्पोरेशन लि०	वानिकी मंजूरी से जुड़ी है।

पर्णपाती वन अनुसंधान संस्थान नीमखेड़ा जबलपुर

2007. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) **मध्य प्रदेश के जबलपुर** जिले में नीमखेड़ा में स्थित **पर्णपाती वन अनुसंधान संस्थान** पर उनकी स्थापना से लेकर **दिसम्बर, 1991 तक कुल कितनी राशि खर्च** की गई है **और भवनों तथा सडकों, जल-आपूर्ति और** वृक्षारोपण के **कार्य पर कुल कितना व्यय किया गया है;**

(ख) **दिसम्बर, 1991 तक संस्थान द्वारा किए गए** अनुसंधान **कार्य का ब्यौरा क्या है और उससे** पर्यावरण तथा वन विकास के **क्षेत्र में क्या लाभ** हुआ है; और

(ग) वर्तमान में इस संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों की श्रेणी-वार संख्या कितनी-कितनी है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क)

1.	कुल व्यय	:	248.21 लाख रुपये
2.	भवनों तथा सड़कों पर दिसम्बर 1991 तक हुआ व्यय	:	52.13 लाख रुपये
3.	जल आपूर्ति पर व्यय	:	6.90 लाख रुपये
4.	वृक्षारोपण पर व्यय	:	8.90 लाख रुपये